राष्ट्रीय संस्करण

CopyRight - Jagran.com

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 75

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 24 अगस्त 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सुस्ती पर '32 सूत्री' प्रहार, आगे और उपाय तैयार

बड़ा फैसला ▶ मंदी की आहट के बीच निवेश बढ़ाने और पूंजी की समस्या को दूर करने को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की कई घोषणाएं

हरिकिशन शर्मा ● नई दिल्ली

आर्थिक मंदी को लेकर चौतरफा हो रही तीखी बहस के बीच मोदी सरकार ने '32 सूत्री' उपायों का एलान कर इसे तत्काल साधने का संकेत दे दिया है। निवेश बढ़ाने के उपाय, ऑटो सेक्टर को राहत से लेकर, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी (तरलता) बढ़ाने और एमएसएमई कंपनियों के फंड की दिक्कत को दूर करने के उपाय शामिल हैं।

वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण ने शुक्रवार को कई कदम उठाए जाने की घोषणा की। इन उपायों के तहत सरकार ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (एफपीआइ) और घरेलू इक्विटी इन्वेस्टर्स पर बढ़ाए गए 'सुपर-रिच' सरचार्ज को वापस लेने का एलान किया है। हालांकि धनी व्यक्तियों पर बढ़ा सरचार्ज फिलहाल जारी रहेगा और इसकी समीक्षा तीन साल बाद होगी। ऑटो सेक्टर में मांग बढ़ाने के लिए सरकारी विभाग नए वाहन खरीदेंगे और एमएसएमई के लंबित सभी जीएसटी रिफंड एक महीने के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही एनबीएफसी तथा बैंकों को अतिरिक्त लिक्विडिटी उपलब्ध कराने और डीपीआइआइटी में पंजीकृत स्टार्ट-अप के लिए एंजल टैक्स का प्रावधान खत्म करने का फैसला किया गया है। वहीं फ्लैट पाने का इंतजार कर रहे लोगों और रियल एस्टेट को मंदी से उबारने के लिए उपायों की घोषणा अगले हफ्ते की जाएगी। सरकार के उपायों के एलान का अंदाजा शुक्रवार को शेयर बाजार को हो गया था, जिसके चलते सेंसेक्स 228 प्वाइंट की बढ़त लेकर बंद हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'कैपिटल मार्केट में निवेश को बढ़ावा देने के लिए शेयर और यूनिट के ट्रांसफर से होने वाले लांग टर्म व शॉर्ट कैपिटल गेन्स पर बढ़े हुए सरचार्ज को हटाने का फैसला किया गया है।' उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को दोहराते हुए कहा कि हम वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान करते हैं। वित्त मंत्री ने पिछले कुछ दिनों में इंडस्ट्री के अलग-अलग सेक्टरों के साथ चर्चा की और उद्योगों की समस्याएं समझने के लिए देशभर में अलग-अलग शहरों का दौरा किया, उसके बाद उन्होंने इन उपायों की घोषणा की है।

उन्होंने इस साल जुलाई में पेश किए गए आम बजट में अमीरों के इनकम टैक्स पर लगने वाले सरचार्ज को बढ़ाया था। उन्होंने 2-5 करोड़ रुपये तक सालाना टैक्सेबल इनकम पर सरचार्ज 15 फीसद से बढ़ाकर 25 फीसद करने और पांच करोड़ रुपये से अधिक के टैक्सेबल इनकम पर सरचार्ज बढ़ाकर 37 फीसद करने का एलान किया था। इसके चलते दो से पांच करोड़ रुपये सालाना इनकम वाले व्यक्तियों पर इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट 39 फीसद और पांच करोड़ रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर 42.74 फीसद हो गया था। इस कदम के चलते 40 फीसद एफपीआइ भी इस बढ़े हुए सरचार्ज के दायरे में आ गए, जिससे उन्होंने भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया था। इसका अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ा।

वित्त मंत्री ने कहा कि एफपीआइ पर अब बढ़ा हुआ सरचार्ज नहीं लगेगा और बजटपूर्व स्थिति बहाल हो जाएगी। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय का कहना है कि बढ़े हुए सरचार्ज को वापस लेने से सरकार के खजाने पर लगभग 1,400 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। यह पूछने पर कि क्या अमीर व्यक्तियों के लिए भी बढ़ा हुआ सरचार्ज हट जाएगा, वित्त मंत्री ने कहा कि देश जब आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा तब सरकार धनी व्यक्तियों पर बढ़े सरचार्ज की समीक्षा करेगी। ऑटो सेक्टर में मांग बढ़ाने के उपायों का एलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अपने सभी विभागों को पुराने वाहनों को बदलकर नये वाहन खरीदने के लिए कहेगी। ऑटो सेक्टर की बिक्री लगातार गिर रही है। माना जा रहा है कि सरकार ने जो उपाय घोषित किए हैं, उससे इस क्षेत्र को राहत मिलेगी। एमएसएमई सेक्टर के सभी लंबित जीएसटी रिफंड 30 दिनों के भीतर जारी किए जाएंगे और आगे चलकर जो भी रिफंड होगा उसे दो माह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 70,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। ऑटो, होम और पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों को आरबीआइ की ब्याज दरों में कटौती का लाभ मिले, इसके लिए बैंक रेपो रेट से लिंक लोन प्रोडक्ट लांच करेंगे। एमएसएमई पर बकाया लोन के मामले सुलझाने के लिए बैंक पारदर्शी वन टाम सेटलमेंट पॉलिसी लाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर्ज प्रवाह बढ़ाने के लिए एक नया संगठन स्थापित किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये निवेश के लिए वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग एक इंटर-मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स का गठन कर रहा है।

ऑटो कंपनियों को मिली राहत की बड़ी डोज ›› पेज -12

₹70,000 करोड़ दिए जाएंगे सरकारी बैंकों को तरलता बढ़ाने के लिए

₹5 लाख करोड़ तक बढ़ेगी बैंकों की कर्ज क्षमता

30 दिन में जीएसटी रिफंड मिलेगा लंबित मामलों में

15 दिनों में लोन खत्म होने का डॉक्यूमेंट ग्राहकों को सौंप देंगे बैंक

एफपीआइ को सरचार्ज में राहत। इसे इसी वित्त वर्ष से लागू माना जाएगा

स्टार्टअप्स और इसके निवेशकों को राहत, नहीं लगेगा एंजेल टैक्स

सीएसआर का उल्लंघन अब अपराधिक मामला नहीं।

आयकर नोटिस, समन आदि जारी करने को केंद्रीकृत प्रणाली

शेयर बाजार में कैपिटल गेन पर सरचार्ज वापस लिया जाएगा

डीमैट खातों में भी आधार की केवाईसी मान्य होगी

होम लोन एवं कार लोन की शर्तें आसान करने का एलान

लोन की अर्जियों पर ऑनलाइन नजर रखी जाएगी

बैंक लोन को रेपो रेट से लिंक करेंगे। रेपो रेट घटते ही घटेगी ब्याज दर

रियल एस्टेट को मंदी से उबारने और फ्लैट का इंतजार कर रहे लोगों के लिए घोषणा अगले हफ्ते

हमारी विकास दर दूसरों से ज्यादा

सरकार ने ये उपाय ऐसे समय में घोषित किए हैं जब जीडीपी ग्रोथ रेट घटकर पांच साल के न्यूनतम स्तर 6.8% पर आ गया है और ऑटो व रियल एस्टेट में प्रोत्साहन पैकेज की मांग उठ रही है। पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 5.8% रह गया है। सीएसओ अगले हफ्ते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी करेगा तो यह और नीचे आ सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत का ग्रोथ रेट विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अब भी सबसे ज्यादा है।

नहीं होने देंगे किसी करदाता का उत्पीड़न

वित्त मंत्री ने दो घंटे चले प्रेस कांफ्रेंस के दौरान आधा दर्जन से अधिक बार 'हरासमेंट' शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा किसी भी अधिकारी को ऐसा कुछ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिससे किसी करदाता को लगे कि उसका हरासमेंट (उत्पीड़न) हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक अक्टूबर 2019 से इनकम टैक्स के सभी नोटिस डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ जारी किए जाएंगे और पुराने नोटिस को भी इस सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा।

सरोकार

जिलाधिकारी ने जंगल में खोज निकाली 'संजीवनी'

रायपुर : दंडकारण्य (बस्तर) में तबादले को अफसर दंड ही मानते आए थे, पर

जिलाधिकारी डॉ. तंबोली अय्याज फकीरभाई ने इसे चुनौती माना। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराईं और गरीबों के मसीहा बन गए। (पेज-10)

जागरण विशेष

अब दोगुना हो जाएगा पतरातू घाटी की सैर का मजा

रामगढ़ : रेलवे ट्रैक बिछ जाने से झारखंड की पतरातू घाटी की सैर का मजा दोगुना हो

जाएगा। रांची से बरकाकाना तक नई रेल लाइन बिछाई जा रही है। इसी साल सांकी स्टेशन से हटिया तक ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। (पेज-10)

भारत-अमेरिका के बीच 'टू प्लस टू' वार्ता की तैयारी शुरू

नई दिल्ली : भारत-अमेरिका के बीच दूसरी रणनीतिक वार्ता की तैयारियां जोरों पर हैं। गुरुवार को दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रालयों के अफसरों के बीच इस बारे में अहम बैठक हुई। भारत व अमेरिका के बीच रणनीतिक वार्ता का नाम 'टू प्लस टू' रखा गया है जिसमें दोनों देशों के विदेश व रक्षा मंत्री अगुआई करते हैं। अमेरिका में हुई इस बैठक में रक्षा और विदेश मामलों से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात हुई है। क्षेत्रीय समस्याओं पर भी दोनों पक्षों ने जानकारियों को साझा किया है। (पेज-4)

पाकिस्तान का एफएटीएफ की काली सूची से बचना मुश्किल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- संस्था के एशिया-प्रशांत समूह ने पाक को आतंकी फंडिंग रोकने में नाकाम पाया
- एपीजी ने इस्लामाबाद को काली सूची सरीखी सूची में डाला

आतंकी फंडिंग और गैर कानूनी तरीके से होने वाले वित्तीय लेनदेन को रोकने के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के एशिया प्रशांत समूह (एपीजी) ने माना है कि पाकिस्तान आतंकी और प्रतिबंधित संगठनों के वित्तीय गर्भ नाल को काटने में नाकाम हो चुका है। ऐसे में एपीजी ने पाक को एक तरह से काली सूची में डालने की सिफारिश कर दी है। आस्ट्रेलिया के कैनबरा में एपीजी की दो दिनी बैठक के बाद जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसका अर्थ यही है कि पाक काली सूची में जाने के और नजदीक पहुंच चुका है। इस बारे में अंतिम फैसला अक्टूबर, 2019 में एफएटीएफ की शीर्ष बैठक में होगा। वहां पाक के बचने की बहुत सूरत तो नहीं दिखती, लेकिन अभी चीन एफएटीएफ का अध्यक्ष है। ऐसे में यह देखना होगा कि चीन एफएटीएफ में उसका बचाव करता है या नहीं।

एपीजी की शुक्रवार को समाप्त हुई बैठक में पिछले तीन माह के दौरान पाकिस्तानी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की समीक्षा करते हुए यह माना गया कि वह 40 में से 32 मानकों पर नाकाम रहा है। इस बैठक के बारे में भारतीय अधिकारियों का कहना है कि आतंकी संगठनों को फंडिंग रोकने में पाकिस्तान का प्रदर्शन सबसे लचर पाया गया है। इसके लिए तय 11 मानकों में से 10 में पाक की तरफ से उठाए गए कदमों को प्रभावशाली नहीं माना गया है। किसी भी मानक में उसके प्रदर्शन में सुधार नहीं किया गया है। इस वजह से उसे एक तरह से 'एनहांस्ड एक्सपेडाइटेड फॉलो अप सूची' में रखा गया है जिसका अर्थ हुआ कि पाकिस्तान प्रतिबंधित सूची में शामिल होने के और करीब आ गया है। वैसे अधिकारी यह भी बताते हैं कि पेरिस में एफएटीएफ की अक्टूबर, 2019 में होने वाली बैठक में अंतिम फैसला होगा। उसकी प्रक्रिया एपीजी से अलग होती है, लेकिन यह तय है कि 41 सदस्यीय एपीजी की बैठक के बाद पाक के खिलाफ एक माहौल बन ही गया है।

खुले आम रैली करता हाफिज सईद फाइल

बताते चलें कि एफएटीएफ की जून, 2019 में हुई बैठक में पाक को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया गया था। साथ ही पाक को चेतावनी भी दी गई थी कि अगर उसने सख्त कार्रवाई नहीं की तो उसके काली सूची में शामिल होने का खतरा रहेगा। एफएटीएफ ने आतंकी फंडिंग रोकने पर की जा रही लापरवाही पर पाक को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा था कि जो दायित्व उसे जनवरी, 2019 तक पूरा करना था उसमें वह नाकाम रहा। सरकार ने जो कार्य योजना दी थी उसका पालन भी मई, 2019 तक नहीं हुआ। ऐसे में उसे चेतावनी देते हुए तीन माह का और समय दिया गया था। यही वजह है कि कुछ जानकार मान रहे हैं कि चीन के एफएटीएफ अध्यक्ष बनने के बावजूद पाक के लिए इस बार काली सूची से बचना आसान नही होगा। सदन रहे कि एफएटीएफ की इस बैठक में सर्बिया को निगरानी सूची से बाहर कर दिया गया था, लेकिन यमन, ईरान, सीरिया, जैसे 12 देशों के साथ पाक को बनाए रखा गया था।

पाकिस्तान ने कहा है कि उसे काली सूची में नहीं डाला गया है। भारत का मीडिया में गलत प्रचार किया जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पाक को एपीजी ने भले ही काली सूची में नहीं रखा है, लेकिन उसे जिस श्रेणी में रखा गया है वह सबसे निचली है। इसके बाद सिर्फ काली सूची ही बचती है।

चरमरा सकती है पाक की अर्थव्यवस्था पेज›› 13

भारत में 'अस्थाई' के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं

- 370 पर पीएम का कांग्रेस पर कटाक्ष, कहा-अस्थाई हटाने में 70 साल लग गए, समझ नहीं आता कि हंसें या रोएं
- नए भारत में आतंकवाद, भाई-भतीजावाद, वंशवाद और जनता के पैसे की लूट पर कसा शिकंजा

यूनेस्को मुख्यालय में भारतीयों को संबोधित करते पीएम मोदी। प्रेट्र

पेरिस, प्रेट्र : फ्रांस की राजधानी पेरिस की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर पर देश और दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया। अनुच्छेद 370 को खत्म करने का परोक्ष उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि भारत में 'टेंपरेरी' यानी अस्थाई के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं है। नए भारत में आतंकवाद के लिए भी कोई जगह नहीं है। रिफॉर्म, परफॉर्म व ट्रांसफॉर्म और स्थाई प्रणालियों के साथ देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री फ्रांस के बाद अगले चरण में यूएई पहुंच गए हैं। जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। यूएई अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ जायद' से भी पीएम मोदी को सम्मानित करेगा। पीएम मोदी यूएई से ही बहरीन भी जाएंगे और फिर रविवार को समूह 7 की बैठक में शामिल होने के लिए फिर फ्रांस लौटेंगे।

प्रधानमंत्री ने पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, उनकी सरकार 'स्पष्ट नीति, सही दिशा' की भावना के साथ काम कर रही है। अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'भारत में अब अस्थाई के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आपने देखा कि 1.25 अरब की आबादी और महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, राम, कृष्ण के देश में अस्थाई व्यवस्था को खत्म करने में 70 साल लग गए। अस्थाई को निकालते-निकालते 70 साल लगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस पर मुझे हंसना या रोना चाहिए।' उन्होंने कहा, नए भारत में हमने आतंकवाद पर लगाम कसी, भाई-भतीजावाद, परिवारवाद, जनता के पैसे की लूट को बंद किया। अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में तीन तलाक कानून जैसे बड़े फैसलों के बारे में बात करते हुए कहा, नया भारत मुस्लिम महिलाओं के साथ तीन तलाक के अन्याय को स्वीकार नहीं कर सकता। मोदी ने कहा, 'चार साल पहले मैं फ्रांस आया था तो मैंने कहा था कि भारत आकांक्षाओं और आशाओं के सफर पर निकल चुका है। आज भारत न सिर्फ उस रास्ते पर निकल चुका है बल्कि सवा अरब भारतवासियों के विश्वास के साथ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि इस बार फिर पहले से भी अधिक प्रचंड जनादेश देकर हमारी सरकार को समर्थन दिया है।'

मोदी-मोदी के लगे नारे पेज›› 3

राजस्थान में वैन पर पलटा एसिड से भरा टैंकर, नौ लोगों की मौत

संवाद सूत्र, उदयपुर

- राजसमंद जिले में हुआ हादसा, मरने वाले सभी एक ही परिवार के

राजस्थान के राजसमंद जिले में बेकाबू हुआ एसिड से भरा टैंकर एक वैन पर पलट गया। इस हादसे में वैन सवार सभी नौ लोगों की मौत हो गई। मृतकों में तीन बच्चे, दो महिलाएं तथा चार पुरुष शामिल हैं। बताया जाता है कि भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बा निवासी परिवार वैन से घूमने निकला था।

जानकारी के मुताबिक, हादसा शुक्रवार दोपहर देसूरी-पाली हाइवे पर हुआ। वैन के ओवरटेक करने के दौरान टैंकर अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे चट्टान से टकराकर वैन पर ही पलट गया। टैंकर से एसिड के रिसाव के चलते काफी देर तक सहायता के लिए वहां तक नहीं पहुंचा जा सका। पानी का छिड़काव करने से एसिड का प्रभाव कम हुआ तब जाकर शवों को बाहर निकाला जा सका। इस कवायद में तीन घंटे लग गए। वैन में सवार सभी नौ लोगों की मौत हो गई। हादसे के कारण हाइवे पर दोनों तरफ पांच घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस के अनुसार हादसे के बाद एसिड सड़क पर फैलने लगा था, इसी दौरान एक बाइक सवार भी टैंकर से टकरा गया। गनीमत रही कि वह बच गया। राजसमंद नगर परिषद से दमकल की गाड़ी बुलवाकर पानी का छिड़काव किया गया। हादसे के बाद राजसमंद कलेक्टर अरविंद पोसवाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुंचे।

एसिड से भरे टैंकर के नीचे दबी वैन में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करते लोग। जागरण

भारतीय मिसाइल का ही शिकार हुआ था वायुसेना का हेलिकॉप्टर

नई दिल्ली : मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले में 27 फरवरी को भारतीय वायुसेना का एमआइ-17 हेलिकॉप्टर भारतीय मिसाइल का ही निशाना बन गया था। न्यायिक जांच में यह साफ हो गया है कि दोस्त और दुश्मन में फर्क न कर पाने के कारण यह आत्मघाती कदम उठाया गया। मामले की जांच के बाद वायुसेना के पांच अफसरों को दोषी पाया गया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में वायुसेना के छह जवानों व एक स्थानीय नागरिक की मौत हो गई थी। (पेज-6)

वाडा ने भारत की राष्ट्रीय डोप टेस्ट लैब को किया निलंबित

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) को डोप टेस्ट करने के लिए मजबूर करने वाली राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की राष्ट्रीय डोप टेस्ट प्रयोगशाला (एनडीटीएल) को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) ने छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है। भारतीय खेल मंत्रालय वाडा के इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। यह भारत के डोपिंग निरोधक कार्यक्रम के लिए बड़ा झटका है। इस लैब को 2008 में ही वाडा से मान्यता मिली थी। (पेज-14)

चिदंबरम को सोमवार तक गिरफ्तार नहीं कर सकता ईडी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आइएनएक्स मामला

- सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक दिया संरक्षण, सीबीआइ मामले में सुनवाई सोमवार तक टाली
- चिदंबरम ने सीबीआइ हिरासत में भेजने को भी दी है चुनौती

भ्रष्टाचार मामले में सीबीआइ हिरासत में मौजूद पूर्व वित्त और गृह मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को थोड़ी राहत मिल गई। शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई यानी सोमवार तक चिदंबरम को मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) में गिरफ्तारी से संरक्षण दे दिया। यानी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सोमवार तक चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकता।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 अगस्त को आइएनएक्स मीडिया मामले में पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने सीबीआइ और ईडी दोनों ही मामलों में अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। चिदंबरम ने दोनों ही आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके अलावा नई विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर उन्हें हिरासत में भेजने के सीबीआइ अदालत के आदेश को भी चुनौती दी है।

शुक्रवार को चिदंबरम की दोनों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर. भानुमति और एएस बोपन्ना की पीठ के सामने सुनवाई पर लगीं थीं। चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, यहां मामला उनके जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से जुड़ा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सुनवाई का मौका नहीं दिया गया इसलिए वह इस याचिका पर बहस करेंगे। सीबीआइ और ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिकाएं महत्वहीन हो चुकी हैं क्योंकि सीबीआइ उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। मेहता ने संविधान पीठ के पूर्व आदेश का हवाला देते हुए कहा, गिरफ्तारी के बाद अग्रिम जमानत अर्जी महत्वहीन हो जाती है, लेकिन सिब्बल बोले-उन्होंने गिरफ्तार होने के बाद अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की होती तो संविधान पीठ का फैसला लागू होता, लेकिन उन्होंने याचिका गिरफ्तारी के पहले ही दाखिल कर दी थी। चिदंबरम ने जांच में पूरा सहयोग किया है इसके बावजूद अदालत ने उन्हें सीबीआइ हिरासत में भेज दिया। उन्होंने अलग से विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर हिरासत में भेजने को चुनौती दी है, कोर्ट उस अर्जी पर भी सुनवाई करे। इन दलीलों पर जस्टिस भानुमति ने कहा, गलत सही जो भी हो, लेकिन एक सक्षम अदालत ने चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआइ हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।

पी. चिदंबरम फाइल फोटो

ऐसे में कोर्ट फिलहाल सीबीआइ के मामले में सुनवाई नहीं करेगा। सीबीआइ से जुड़ी दोनों अर्जियों पर सोमवार को सुनवाई की जाएगी।

इसके बाद चिदंबरम के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामले पर बहस शुरू हुई। हाई कोर्ट ने इस मामले में भी चिदंबरम की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। हालांकि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। सिब्बल ने कहा, मामले में बहस पूरी होने तक ईडी की ओर से जमानत अर्जी का जवाब दाखिल नहीं किया गया। जब बहस पूरी हुई तब ईडी ने कोर्ट में एक नोट दाखिल किया और न्यायाधीश ने सात महीने आदेश सुरक्षित रखने के बाद याचिका खारिज करने वाले आदेश में ईडी के नोट में लगाए गए आरोप हूबहू उतार दिए। ईडी ने उसमें जो आरोप लगाए थे, जैसे तीन करोड़ रुपये खाते में आए आदि, सब आदेश में शामिल कर दिए। उन्हें आरोपों का जवाब देने का मौका भी नहीं दिया गया और हाई कोर्ट ने उसी नोट के आधार पर अग्रिम जमानत खारिज कर दी। चिदंबरम के दूसरे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, जज ने आदेश में यहां तक लिखा कि आर्थिक अपराधों के मामले में अग्रिम जमानत का प्रावधान खत्म कर दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यह प्रावधान खत्म हुआ था जिसे जून से फिर प्रभावी किया गया है।

चिदंबरम ने अपने बेटे को लाभ देने के लिए कहा था : प्रवर्तन निदेशालय पेज›› 4

मोदी के 'संवाद मैजिक' की काट तलाशे कांग्रेस

पार्टी में उठी मांग

जयराम के बाद सिंघवी और थरूर भी मोदी के खिलाफ सिर्फ नकारात्मक प्रचार के पक्ष में नहीं, विश्वसनीयता के साथ अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक तरीके की तलाश पर जोर

संजय मिश्र, नई दिल्ली

कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद मैजिक का मुकाबला करने की रणनीति पर अब खुली राय जाहिर करने से परहेज नहीं किया जा रहा है। वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के बाद अभिषेक मनु सिंघवी और शशि थरूर सरीखे वरिष्ठ नेता भी कहने लगे हैं कि केवल नकारात्मक प्रचार से मोदी का कारगर सियासी मुकाबला नहीं किया जा सकता। पीएम के प्रभावी संवाद संप्रेषण के अंदाज को देखते हुए पार्टी में तमाम नेता इस राय के हिमायती हैं कि अपनी बात विश्वसनीयता के साथ जनता तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक तरीका ढूंढ़ना ही होगा। साथ ही पार्टी को राजनीतिक मुद्दों के साथ संवाद शैली की नई रणनीति पर मंथन कर इसका रास्ता निकालना पड़ेगा।

पीएम मोदी के संवाद की ताकत के साथ उनको खलनायक के रूप में पेश करने से बचने की जयराम रमेश, अभिषेक सिंघवी और शशि थरूर के बयान पर भले पार्टी में बाहरी हलचल हो मगर अंदरूनी तौर पर कांग्रेस में इनकी राय से सहमत होने वाले नेताओं की तादाद काफी है। इन नेताओं की बात से सहमति जाहिर करते हुए पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, वैसे तो लोकसभा चुनाव से पहले ही जनता से 'कनेक्ट' करने की मोदी की क्षमता हमारे लिए चुनौती रही है। मगर अब चुनौती ज्यादा गंभीर इसीलिए है कि कांग्रेस और विपक्ष की तार्किक बातें भी जनता में प्रभाव नहीं बना पा रहीं। वहीं मोदी की आधी-अधूरी सच्चाई भी लोगों को विश्वसनीय लगती हैं।

कांग्रेस के एक पुराने दिग्गज ने कहा, 'बातों के जादूगर' मोदी के युग में विपक्ष की बात लोगों को विश्वसनीय लगे इसके लिए संप्रेषण का 'एप्रोच' बदलना समय की जरूरत है। इस फैक्टर की विपक्षी पार्टियां कब तक अनदेखी कर सकती हैं कि आर्थिक समेत कई मोर्चे पर सरकार के उदासीन प्रदर्शन के बाद भी मोदी के अंदाजे बयां की वजह से सत्ता विरोधी जैसा मानस बनने की सूरत नहीं दिख रही। संवाद के मैजिक का ऐसा प्रभाव राजनीति के मौजूदा दौर में एक नई स्थिति है।

ऐसे में विपक्ष खासकर कांग्रेस को इस स्थिति को केवल राजनीतिक ही नहीं मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और तर्कशास्त्र की कसौटी पर परखने की जरूरत है। इस लिहाज से शशि थरूर और सिंघवी की इस राय में दम है कि जब मोदी कोई अच्छा काम करते हैं तो उसकी तारीफ करने से गुरेज नहीं करना चाहिए ताकि जब हम सरकार की नाकामी को उजागर करें तो विपक्ष की आवाज भी विश्वसनीयता से ली जाए।

वैसे दिलचस्प यह है कि मोदी पर नकारात्मक प्रहार का कांग्रेस कई बार सियासी नुकसान राष्ट्रीय राजनीति ही नहीं गुजरात की सियासत में भी उठा चुकी है।

सबसे पहले 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी की शिकस्त की एक बड़ी वजह नरेंद्र मोदी को 'मौत का सौदागर' बताने की सोनिया गांधी की टिप्पणी रही। इसी तरह 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की मोदी को चायवाला बताने की टिप्पणी रही। अय्यर के इस वार को मोदी ने लपकते हुए 'चाय पर चर्चा' का ऐसा जवाबी दांव चला कि अभी तक कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दिलचस्प यह है कि एक बार फिर मोदी पर अय्यर की 'नीच' टिप्पणी 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए भारी पड़ी। इसी तरह हालिया लोकसभा चुनाव में मोदी पर 'चौकीदार चोर है' का राहुल गांधी के वार का दांव उल्टा पड़ गया। कांग्रेस के कई नेताओं ने खुले तौर पर चुनाव के बाद 'चौकीदार चोर है' नारे का नुकसान होने की बात कही भी।